(ii) Liberalisation of the acquisition norms;

(iii) Allowing shipowners to place orders on Indian Shipyards without reference to assessed requirements;

(iv) Providing cargo support to Indian Shipping;

(v) Modification of *pari-passu* abligations;

(vi) Rehabilitation of sick but viable shipping companies.

(vii) During April, 1987 to 30th June, 1989 Private Companies have been given approvals to acquire 135 ships out of which 37 ships have been acquired.

(viii) Shipping Corporation of India has currently on order 15 ships aggregating to 5.03 lakh DWT either for itself or on behalf of other Government agencies.

(ix) A specialised financing institution viz. Shipping Credit & Investment Company of India (SCICI) has been formed to provide finance for ship acquisition by private companies.

Acquisition of ships

1753. SHRI YASHWANT SINHA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on account of severe foreign exchange crisis no new acquisition of ships is being allowed by Government at present; and

(b) the additional shipping tonnage proposed to be acquired during the Eighth Five Year Plan period?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT): (a) No, Sir.

(b) This will be known when the 8th Five Year Plan is finally approved.

मध्य प्रदेश में मीटर रेल लाइन का बड़ी रेल लाइन में परिवर्तन

1754. **श्रीमती रत्न कुमारी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में कौन-कौन से क्षेत्रों में मीटर रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का कार्य चल रहा है; और

(ख) क्या सारा कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप चल रहा है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) मध्य प्रदेश में मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कोई नई परियोजनाएं नहीं हैं।

गंज बासोदा पर रुकने वाली अप और डाउन रेलगाड़ियां

1755. **श्री अशोक नाथ वर्मा:** क्या रेलमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य रेलवे के "गंज बासोदा" रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली अप और डाउन रेलगाड़ियों के नाम क्या-क्या हैं और प्रत्येक रेलगाड़ी में इस शहर के लिए आरक्षण का कितना कोटा है; और

(ख) क्या बम्बई और दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए आरक्षण कोटे में वृद्धि किए जाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) गंज बासोदा पर ठहरने वाली अप और डाउन गाड़ियों के नाम और प्रत्येक गाड़ी में किये गये आरक्षण कोटे की व्यवस्था को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिये)।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

गंज बासोदा स्टेशन पर ठहरने वाली अप और डाउन गाड़ियों के नाम	दूसरा दर्जा	
	सीटें	शयतकाएं
1. 167 डाउन मालवा एक्सप्रेस	—	4
2. 168 अप मालवा एक्सप्रेस	—	—
3. 37 डाउन पंजाब मेल	—	5
4. 38 अप पंजाब मेल	—	4
5. 57 डाउन दादर अमृतसर एक्सप्रेस	—	2
6. 58 अप अमृतसर-दादर एक्सप्रेस	—	1
7. 35 डाउन-भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस एवं पैसेंजर गाड़ी	—	—
8. 36 अप बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस एवं पैसेंजर	—	—
9. 21 डाउन निजामुद्दीन-हैदराबाद एक्सप्रेस	—	2
10. 22 अप हैदराबाद-निजामुद्दीन एक्सप्रेस	—	2
11. 115 अप बम्बई-गोरखपुर एक्सप्रेस	—	—
12. 116 डाउन गोरखपुर-बम्बई एक्सप्रेस	—	—
13. 94 डाउन भोपाल-कोटा पैसेंजर	—	—
14. 93 अप कोटा-भोपाल पैसेंजर	—	—
15. 355 डाउन इटारसी-झांसी पैसेंजर	—	—
16. 356 अप झांसी-इटारसी पैसेंजर	—	—
17. 89"ए" डाउन भोपाल-बीना पैसेंजर	—	—
18. 90"ए" अप बीना-भोपाल पैसेंजर	—	—

Australian initiative on mining and oil drilling in the Antarctica

1756. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether India has communicated its willingness to support Australia's initiative to bring about a comprehensive plan on mining, oil drilling and other developmental activities in the Antarctica; and

(b) if so, what are the main points of Australia's move and to what extent it has been accepted by the Indian Government?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) and (b) A convention on the Regularation of Antarctica Minerals Resources Activities was adopted in 1988 by the Antarctic Treaty Consultative Parties in May 1989, the Australian Government announced that it would not sign the recently adopted Convention Australia has also indicated its preference for a complete ban on mining activities. and converting the Antarctic into a Wilderness Park. India is prepared to consider any proposal which would lead to an